क्रमांक 15011/35/2021-जेयूएस(एयू)/ई5903

भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

जैसलमेर हाउस, 26मान सिंह रोड,

नई दिल्ली-110011

दिनांक: 28 दिसंबर, 2021

कार्यालय ज्ञापन

विषय: मंत्रिमंडल के लिए नवंबर, 2021 माह के मासिक सार के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को एतद्द्वारा न्याय विभाग के नवंबर, 2021 माह के मासिक सार की एक प्रति परिचालित करने का निदेश हुआ है।

2. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(एम एस पी दारा)

अवर सचिव (समन्वय)

संलग्न: यथोपरि।

प्रतिः

1. मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य।
2. उपाध्यक्ष, नीति आयोग, संसद मार्ग, नई दिल्ली।

प्रतिलिपि:

संयुक्त सचिव (श्री संदीप सरकार), कैबिनेट सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।

प्रतिलिपि सूचनार्थ अग्रेषितः

1. अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, शाहजहाँ रोड, नई दिल्ली।
2. भारत के राष्ट्रपति के सचिव, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
3. भारत के उपराष्ट्रपति के सचिव, मौलाना आज़ाद रोड, नई दिल्ली।
4. भारत सरकार के सभी सचिव।
5. विधि एवं न्याय मंत्री के निजी सचिव, शास्त्री भवन, नई दिल्ली ,
6. विधि एवं न्याय राज्य मंत्री के निजी सचिव, शास्त्री भवन, नई दिल्ली

भारत सरकार

विधि एवं न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

विषय: न्याय विभाग के संबंध में नवंबर, 2021 माह का मासिक सार।

न्याय विभाग की नवंबर, 2021 माह की महत्वपूर्ण गतिविधियाँ निम्नलिखित हैं।

1. आजादी का अमृत महोत्सव:

- न्याय विभाग ने आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 8-14 नवंबर, 2021 के आवंटित सप्ताह के दौरान कई कार्यक्रम आयोजित किए हैं। इस सप्ताह के दौरान, विभाग ने अपने टेली-लॉ: रीचिंग द अनरीच्ड के तहत लॉगिन सप्ताह अभियान शुरू किया, ताकि उनके अधिकारों का सही ढंग से दावा करने और उनकी कठिनाइयों के समय पर निवारण के लिए पूर्व-मुकदमेबाजी सलाह तक पहुंच में वृद्धि को बढ़ावा दिया जा सके। 4200 जागरूकता सत्रों के माध्यम से 52000 से अधिक लाभार्थियों तक पहुंचा गया और लगभग 17000 व्यक्तियों को टेली-लॉ के तहत वीडियो/कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं के माध्यम से पैनल वकीलों के एक समर्पित पूल द्वारा कानूनी सलाह और परामर्श प्रदान किया गया। पहुंच को अधिकतम करने के लिए टेली-लॉ ऑन व्हील्स अभियान भी चलाया गया, जहां विशेष टेली-लॉ ब्रांडेड मोबाइल वैन ने वीडियो, रेडियो जिंगल और टेली-लॉ पत्रक के वितरण के माध्यम से टेली-लॉ का संदेश फैलाने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में यात्रा की।

- 13 नवंबर को विभाग द्वारा एक मेगा कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था जिसमें 65,000 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया था और इसकी अध्यक्षता माननीय विधि और न्याय मंत्री और माननीय राज्य मंत्री ने की थी। इस अवसर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 126 फ्रंट-लाइन पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया, जिनके देश के दूर-दराज के इलाकों में अथक प्रयासों से टेली लॉ को गौरवशाली ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद मिली है। पैनल वकीलों के साथ लाभार्थियों के निर्बाध कनेक्शन को सक्षम करने के लिए एक टेली-लॉ मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है। नागरिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रिंट और डिजिटल ज्ञान उत्पाद जारी किए गए जिनमें टेली-लॉ ब्रोशर, टेली-लॉ फिल्में, टेली-लॉ लोगो और टेली-लॉ मैस्कॉट शामिल हैं।

- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) ने भी अनेक कार्यक्रम आयोजित किए थे। 9 नवंबर को पूरे देश में विधिक सेवा दिवस मनाया गया। 14 नवंबर को "अखिल भारतीय कानूनी जागरूकता और आउटरीच अभियान" के लिए समापन समारोह आयोजित किया गया था। इस अभियान के एक भाग के रूप में, 83 करोड़ नागरिकों तक पहुँचने के लिए घर-घर जाकर दौरा किया गया। लगभग 6 लाख जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए जिससे 26 करोड़ नागरिकों को लाभ हुआ। 39,000 से अधिक कानूनी सहायता क्लिनिक आयोजित किए गए जिससे लगभग 1.50 करोड़ नागरिकों को सहायता मिली। 3.21 लाख गांवों में 26,460 मोबाइल वैन तैनात की गईं, जिन्होंने 19 करोड़ नागरिकों को कानूनी सहायता सेवाओं के बारे में जागरूक किया।

- न्याय विभाग ने 8 से 14 नवंबर, 2021 तक पूर्वोत्तर राज्यों अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और मणिपुर में कानूनी साक्षरता सप्ताह भी आयोजित किया। जागरूकता और संवेदीकरण गतिविधियों से 20,000 से अधिक प्रतिभागियों को लाभ हुआ

2. **संविधान दिवस, 26 नवंबर, 2021 का स्मरणोत्सव**

- दिनांक 26.11.2021 को संविधान दिवस समारोह के अवसर पर न्याय विभाग के कर्मचारियों और सदस्यों को भारत के संविधान की प्रस्तावना को पढ़ने और भारत के माननीय राष्ट्रपति के साथ शपथ ग्रहण समारोह में 'लाइव' शामिल होने में सक्षम बनाने के लिए जैसलमेर हाउस में व्यवस्था की गई थी। आम आदमी के जीवन में संविधान के महत्व को लोकप्रिय बनाने के लिए, "मौलिक कर्तव्यों' पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, मुंबई के कुलपति और नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु के रजिस्ट्रार ने प्रतिभागियों को मौलिक कर्तव्यों की दार्शनिक पृष्ठभूमि, मौलिक कर्तव्यों पर संवैधानिक प्रावधानों और कोविड के समय में मौलिक कर्तव्यों का पालन करने की आवश्यकता के बारे में बताने के लिए हिस्सा लिया। वेबिनार के माध्यम से टेली-लॉ-प्रोग्राम के फ्रंट लाइन पदाधिकारियों (पैरा लीगल वालंटियर्स, ग्राम स्तर के उद्यमियों और पैनल वकीलों) सहित 24,000 से अधिक प्रतिभागियों तक पहुंच बनाई गई।

3. **सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश (वेतन और सेवा की शर्त) अधिनियम 1958 और उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1954 में संशोधन:**

- सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम 1958 और उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1954 में संशोधन दिनांक 30.11.2021 को लोकसभा में पेश किया गया था।

4. **बुनियादी ढांचे के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना:**

- दिनांक 10.11.2021 को पीएफएमएस के माध्यम से सीएसएस के तहत धन जारी करने की प्रक्रिया के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा करने के लिए राज्य सरकारों/उच्च न्यायालयों के प्रतिनिधियों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस बैठक आयोजित की गई थी। वर्तमान में, न्यायिक बुनियादी ढांचे के लिए सीएसएस के तहत, 6089 कोर्ट हॉल (पूर्ण और निर्माणाधीन) और 4813 आवासीय इकाइयां (पूर्ण और निर्माणाधीन) न्याय विकास 2.0 पोर्टल के साथ जियोटैग की गई हैं।

5. **फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (एफटीएससी):**

- राज्यों और उच्च न्यायालयों के साथ निरंतर अनुवर्ती कार्रवाई के परिणामस्वरूप, 381 विशिष्ट पोक्सो अदालतों सहित 681 फास्ट ट्रैक कोर्ट 27 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यरत हैं और डैशबोर्ड से प्राप्त इनपुट के अनुसार, नवंबर, 2021 तक इन फास्ट ट्रैक कोर्टों द्वारा कुल 64217 मामलों का निपटारा किया गया।

6. **ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना चरण- II:**

- वृहत् क्षेत्र नेटवर्क: बीएसएनएल ने 2992 कॉम्प्लेक्स में से 2956 कोर्ट कॉम्प्लेक्स को 10 एमबीपीएस से 100 एमबीपीएस बैंडविड्थ स्पीड के साथ चालू किया है।

- वर्चुअल कोर्ट रूम: दिनांक 01-11-2021 को, उड़ीसा राज्य के अंगुल और नयागढ़ जिलों में उड़ीसा उच्च न्यायालय की एक पहल, 'मॉडल वर्चुअल कोर्ट' का उद्घाटन किया गया। इन अदालतों से जुड़ा सबसे बड़ा लाभ यह है कि किसी भी स्थान से गवाहों के साक्ष्य की रिकॉर्डिंग की जा सकती है ताकि मुकदमा

बिना किसी बाधा के आगे बढ़ सके, और गवाहों के पेश होने के लिए विशिष्ट समय-स्लॉट हो सकते हैं ताकि किसी के समय की बर्बादी न हो। वे साक्ष्यों की रिकॉर्डिंग से निपटने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित हैं; उनमें गवाह आदि को दस्तावेज़ दिखाने के लिए एक विज़ुअलाइज़र है।

- राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड: ई-कोर्ट सेवा मंच के माध्यम से, वादीगण 19.56 करोड़ से अधिक मामलों और 15.72 करोड़ से अधिक आदेशों/निर्णयों के संबंध में मामले की स्थिति की जानकारी तक पहुंच सकते हैं।

- वर्चुअल कोर्ट: 15 वर्चुअल कोर्टों द्वारा 99 लाख से अधिक (99,54,216) मामलों को निपटाया गया है और दिनांक 01.11.2021 तक 18 लाख से अधिक (18,37,985) मामलों में 193 करोड़ रुपये से अधिक (193.15 करोड़ रुपये) की ऑनलाइन वसूली की गई है।

- ई-समिति की वेबसाइट अंग्रेजी के अलावा बारह क्षेत्रीय भाषाओं में लाइव: उच्च न्यायालयों के समन्वित प्रयास से, ई-समिति की वेबसाइट अब 12 क्षेत्रीय भाषाओं और अंग्रेजी में लाइव है, जिससे दिनांक 31.08.2021 तक कुल 13 भाषाएँ हो गई हैं।

- वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के नियमों का कार्यान्वयन: कुल 21 उच्च न्यायालयों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियमों को लागू किया है। इसके अतिरिक्त, 28 उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के तहत, 23 जिला न्यायालयों ने दिनांक 31.08.2021 तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियमों को अपनाया है।

- ई-फाइलिंग के नियमों का कार्यान्वयन: 28 उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के तहत, 11 जिला न्यायालयों ने दिनांक 31.08.2021 तक ई-फाइलिंग के मॉडल नियमों को अपनाया है।

- राष्ट्रीय सेवा और इलेक्ट्रॉनिक समन की ट्रैकिंग (एनएसटीईपी) और ई-भुगतान: दिनांक 31.08.2021 तक, 17 उच्च न्यायालयों ने एनएसटीईपी लागू कर दिया है। 15 उच्च न्यायालयों ने ई-भुगतान और 22 उच्च न्यायालयों में कोर्ट फीस अधिनियम में संशोधन पहले ही लागू कर दिया है।

- ई सेवा केंद्र: 31 जुलाई, 2021 तक, 20 उच्च न्यायालयों में 365 ई सेवा केंद्र चालू हो गए हैं। इन्हें ई-कोर्ट परियोजना के साथ-साथ राज्य निधि से भी वित्त पोषित किया गया है।

- **ई कोर्ट मोबाइल ऐप: ई कोर्ट मोबाइल ऐप में 1 नवंबर, 2021 तक कुल 68.04 लाख डाउनलोड दर्ज किए गए हैं।**

- **ई कोर्ट्स सर्विसेज मोबाइल ऐप: दिनांक 27.11.2021 को विज्ञान भवन में भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन.वी. रमन द्वारा एक बहुभाषी ईकोर्ट्स सर्विसेज मोबाइल संस्करण 2.0 लॉन्च किया गया था।**

7. व्यापार करने में आसानी:

- **बॉम्बे हाई कोर्ट ने "वाणिज्यिक न्यायालयों" की वेबसाइट अर्थात "https://bombayhighcourt.nic.in / bhc_commercialcourts / index.php" को सक्रिय और लाइव कर दिया है। इन वेबसाइटों को दिए गए लिंक से या बॉम्बे हाई कोर्ट की वेबसाइट पर दिए गए लिंक से लिया जा सकता है।**

8. न्याय बंधु (प्रो बोनो लीगल सर्विसेज):

- **नवंबर माह के दौरान न्याय बंधु मोबाइल एप्लिकेशन/वेब पोर्टल के माध्यम से 97 नए वकीलों ने पंजीकरण कराया। 23 राज्य बार काउंसिल से कुल 3603 वकीलों (पुरूष - 3169, महिला - 432, ट्रांसजेंडर - 02) ने इस कार्यक्रम के तहत पंजीकरण कराया है। न्याय बंधु पैनल के अंतर्गत 14 उच्च न्यायालयों द्वारा अब तक 463 प्रो बोनो वकीलों को नामांकित किया गया है।**

*****